जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

अजमेर

Rashtradoot

फोनः- 2627612, 2427249 फैक्सः- 0145-2624665 वर्षः 29 संख्याः 359 प्रभात अजमेर, बुधवार 30 जुलाई, 2025 आर.जे./ए.जे./73/2015-2017 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

प्रधानमंत्री से 35 मिनट मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल के परिवर्तन की संभावना पूर्णतया खत्म हुई

भजनलाल जयपुर से अपनी सरकार के निर्णय व क्रियान्वयन की विस्तृत जानकारी देने के लिए कई फाइल्स लाये थे

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 29 जुलाई। दिल्ली और जयपुर में चल रही इन अटकलों, कि राजस्थान में नेतृत्व परिवर्तन होने वाला है, के विपरीत सूत्रों का कहना है कि फिलहाल भाजपा हाईकमान की ओर से मुख्यमंत्री भजनलाल को हटाकर किसी अन्य को लाने की कोई योजना नहीं है।

- प्रधानमंत्री से 35 मिनट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल ने 5 घंटे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला के कमरे में व्यतीत किये।

मुख्यमंत्री भजनलाल ने आज सुबह संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से 35 मिनट की मुलाकात की, जिसके बाद उन्होंने संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला के कार्यालय में लगभग 5 घंटे बिताए।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की।

सूत्रों के मुताबिक, भजनलाल प्रधानमंत्री से मिलने के लिए एक विस्तृत फाइल के साथ पहुंचे, जिसमें उनकी सरकार के फैसले, कार्यवाहियाँ और गतिविधियाँ शामिल थीं। इसका उद्देश्य राज्य में उनके आलोचकों द्वारा लगाये जा रहे अक्षमता के आरोपों और नेतृत्व परिवर्तन की मांगों का जवाब देना था।

यह भी बताया जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे कुछ समय से प्रधानमंत्री से मिलने के लिए समय मांग रही थीं, और जब उन्हें यह समय मिल गया, तो भजनलाल ने भी दिल्ली आने का फैसला किया।

संभवतः उन्हें यह आभास था कि वसुंधरा राजे प्रधानमंत्री से उनके काम-काज की शिकायतें करेंगी, इसीलिए भजनलाल पूरी तैयारी के साथ दिल्ली पहुंचे थे, ताकि वे केन्द्रीय नेतृत्व के सामने अपना पक्ष मजबूती से रख सकें।

दिल्ली में राजस्थान को लेकर चल रही गतिविधियों को देखते हुए, भाजपा सूत्रों का कहना है कि फिलहाल भजनलाल की कुर्सी को कोई खतरा नहीं है।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

एसआई भर्ती पेपर लीक में सुनवाई जारी

जयपुर, 29 जुलाई। राजस्थान हाईकोर्ट में मंगलवार को एसआई भर्ती-2021 पेपर लीक मामले में सुनवाई जारी रही। जस्टिस समीर जैन ने अदालती समय पूरा हो जाने के कारण मामले की सुनवाई आगामी दिनों के लिए टाल दी।

- हाई कोर्ट का समय पूरा होने तक याचिकाकर्ताओं की बहस पूरी नहीं हुई।

सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता कैलाशचन्द व अन्य की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मेजर आरपी सिंह और अधिवक्ता हरेन्द्र नील ने पक्ष रखा। याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि भर्ती परीक्षा का पेपर परीक्षा के दिन से काफी पहले ही आरपीएससी से लीक हो गया था। ऐसे में यह व्यापक स्तर पर अभ्यर्थियों के पास पहुंचा था, जिससे भर्ती परीक्षा की सुचिता और शुद्धता भंग हो गई थी। मामले में एसओजी ने आरपीएससी के सदस्यों तथा ट्रेनी एसआई सहित, अन्य लोगों को गिरफ्तार किया है। ऐसे में परीक्षा को रद्द किया जाना चाहिए।

मोदी ने चोल साम्राज्य की गौरव गाथा में उत्साह से शामिल होकर द्रमुक का प्रचार बेअसर किया

द्रमुक अक्सर आरोप लगाती है कि भाजपा तमिलनाडु की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को खत्म करना चाहती है

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 29 जुलाई। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की हाल ही में संपन्न हुई दो दिवसीय तमिलनाडु यात्रा ने भाजपा और अन्नाद्रमुक के रिश्तों में फिर से मधुरता ला दी है। यह दोनों पार्टियाँ अप्रैल 2021 के विधानसभा चुनावों से पहले सीट बंटवारे को लेकर अलग हो गई थीं।

राज्य में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए, दोनों दलों के बीच के इस मेल-मिलाप को दोनों के लिए सकारात्मक संकेत माना जा रहा है।

दोनों दलों के बीच बढ़ती निकटता के संकेत तब देखने को मिले, जब ईके पलानीस्वामी (ईपीएस) समेत अन्नाद्रमुक के कई वरिष्ठ नेता, जैसे कि के.पी. मुनुसामी, एस.पी. वेलुमणि और थलैवी सुंदरम, प्रधानमंत्री मोदी से एयरपोर्ट पर मिले।

दिलचस्प बात यह रही कि पूर्व अन्नाद्रमुक नेता ओ. पन्नीरसेल्वम (ओपीएस) को मोदी से मिलने की अनुमति नहीं दी गई। एक अन्नाद्रमुक नेता ने कहा, "मोदी द्वारा पन्नीरसेल्वम से न मिलना भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए यह संकेत है कि भाजपा अगला चुनाव लडने में अपने मौजूदा गठबंधन को प्राथमिकता दे रही है।"

- प्र.मंत्री की तमिलनाडु यात्रा से अन्नाद्रमुक और भाजपा के बीच में जमीनी स्तर पर आपसी सामंजस्य और परस्पर सौहार्द्र बढ़ा है, खासकर दोनों दलों के कार्यकर्ताओं के बीच संबंध बेहतर बने हैं।
- मोदी के त्रिची में हुए रोड शो की सफलता सुनिश्चित करने में अन्नाद्रमुक के कैडर ने जोरदार प्रयास किए, इससे यह संकेत मिला कि भाजपा के साथ चुनाव लड़ने के बारे में अन्नाद्रमुक में जो अनिच्छा थी वह अब खत्म हो गई है।
- इसके अलावा प्रधानमंत्री ने अन्नाद्रमुक के पूर्व नेता पन्नीरसेल्वम से मिलने से इन्कार करके संकेत दिया कि भाजपा को अन्नाद्रमुक की अंदरूनी खींचतान से कोई लेना-देना नहीं है।

राज्य के भाजपा कार्यकर्ता इस बात को लेकर उत्साहित हैं कि मोदी ने 'आदि तिरुवधिरई' महोत्सव में भाग लिया, जो चोल वंश की विरासत को उजागर करता है। यह द्रमुक (डीएमके) के कीलाडी नैरेटिव के मुकाबले एक सशक्त सांस्कृतिक जवाब माना जा रहा है। द्रमुक अक्सर भाजपा पर तमिलनाडु की सांस्कृतिक विरासत को कमजोर करने का आरोप लगाती रही है।

भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि मोदी की यात्रा ने भाजपा और

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है'

प्र.मंत्री मोदी ने कहा, अगर पाक ने आतंकी हरकत की तो फिर से सैन्य कार्यवाही की जाएगी

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 29 जुलाई। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को पाकिस्तान को सख्त चेतावनी दी कि यदि वह भारत में आतंकी हमलों के लिए आतंकवाद को बढ़ावा देना बंद नहीं करता, तो भारत की सैन्य कार्रवाई जारी रहेगी।

- लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा पर अपने 100 मिनट के जवाब में प्र.मंत्री ने कहा, विश्व के किसी भी नेता ने पाक पर सैन्य कार्यवाही रोकने के लिए नहीं कहा था।
- मोदी ने कहा, भारत, न्यूक्लियर अटैक की पाकिस्तान की धमकी से रूकने वाला नहीं है। भारत की प्रतिक्रिया पहले से भी मजबूत व आक्रामक होगी।

लोकसभा में पहलगाम आतंकी हमले और उससे जुड़े मुद्दों पर दो घंटे की बहस का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने अपने 100 मिनट के भाषण में स्पष्ट किया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी समाप्त नहीं हुआ है, और जब भी पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद सिर उठाएगा, यह ऑपरेशन फिर से सक्रिय किया जाएगा।

प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भारत, पाकिस्तान की परमाणु हमले की धमकियों से डरने वाला नहीं है। उन्होंने पाकिस्तान द्वारा फैलाए जा रहे झूठे प्रचार की कड़ी आलोचना की और कहा कि कोई भी वैश्विक नेता भारत से युद्ध रोकने को नहीं कह रहा है। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के कथित हस्तक्षेप की अफवाहों को भी खारिज किया।

गृह मंत्री अमित शाह ने भी लोकसभा में कहा कि यह दुष्प्रचार बंद किया जाए कि भारत ने पहलगाम हमलावरों की पहचान नहीं की। उन्होंने बताया कि हमले में शामिल तीन आतंकियों को 28 जुलाई को ही मार गिराया गया।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पाकिस्तान को यह समझ लेना चाहिए कि भारत की प्रतिक्रिया अब और अधिक कठोर और निर्णायक होगी। उन्होंने विपक्ष से भी अपील की कि वे किसी भी प्रकार से पाकिस्तान का समर्थन या उसका प्रचार न करें।

टोंक के जर्जर विद्यालयों की शीघ्र मरम्मत की माँग

टोंक, 29 जुलाई। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव, पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं टोंक विधायक सचिन पायलट ने प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री को पत्र लिखकर टोंक विधानसभा क्षेत्र के जीर्ण-शीर्ण एवं जर्जर अवस्था में मौजूद सरकारी विद्यालयों में शीघ्र मरम्मत कार्य प्रारम्भ करवाने की मांग की है।

- सचिन पायलट ने राज्य के मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री को पत्र लिखा।

पायलट ने अपने पत्र में टोंक विधानसभा क्षेत्र में जर्जर घोषित हुए सरकारी विद्यालयों हेतु नवीन भवन बनवाने तथा मेजर एवं माइनर रिपेरिंग की आवश्यकता वाले माध्यमिक एवं प्रारम्भिक सरकारी विद्यालयों में शीघ्र मरम्मत कार्य करवाने की मांग की है।

पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर विपक्ष ने लोकसभा में सरकार को घेरा

लोकसभा में विपक्ष द्वारा एक आवाज में सरकार की क्षमता व जवाबदेही पर सवाल उठाना एक स्वागत योग्य कदम कहा जा सकता है

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 29 जुलाई। सोमवार और मंगलवार को संसद के दोनों सदनों-लोकसभा और राज्यसभा-में विपक्ष ने एकजुट होकर मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला। विपक्ष ने जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकी हमले को लेकर सरकार पर पूरी तरह विफल होने का आरोप लगाया।

समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव ने सरकार पर नतीजों पर फोकस करने की बजाय, ऑपरेशन महादेव जैसे सैन्य अभियानों का राजनीतिककरण करने का आरोप लगाया। उन्होंने इन हाइप्रोफाइल आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन के उद्देश्य व नतीजों पर स्पष्टीकरण मांगा।

- समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश ने कहा, मोदी सरकार राष्ट्रवाद की नारेबाजी की आड में सच्चाई नहीं छुपा सकती है, लोगों को यह जानने का हक है कि किसने निर्दोष पर्यटकों को मारा और यह सब कैसे हुआ।
- अखिलेश ने आरोप लगाया कि सरकार आपरेशन महादेव जैसी सैन्य कार्यवाहियों का राजनैतिककरण कर रही है। नतीजों पर उसका ध्यान नहीं है।
- तृणमूल सांसद सयानी घोष ने कहा, हम लोकतंत्र है, प्रचार मशीन नहीं, मोदी सरकार को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए। सरकार "हाई वोल्टैज प्रोपैगैंडा" में विश्वास रखती है।
- द्रमुक सांसद कनिमोई ने सरकार पर सूचनाएं छिपाने का आरोप लगाया।

उन्होंने आतंरिक सुरक्षा विफलता को मोदी सरकार के सामरिक रुख से जोड़ते हुए कहा, सरकार राष्ट्रवाद की नारेबाजी की आड़ में नहीं छुप सकती, जबकि यह अपने ही लोगों की रक्षा नहीं कर पाई। देश को यह बताइए कि पिछले 11 वर्षों में चीन ने कितनी जमीन कब्जाई है?"

अखिलेश ने मांग की कि केन्द्र पहलगाम हमलावरों का ब्यौरा दे और बताए कि क्या इस हमले की पूर्व चेतावनी थी, जिसकी अनदेखी की गई। उन्होंने पूछा, जनता को यह जानने का हक है कि किसने निर्दोष पर्यटकों को मारा। अगर हमारा खुफिया तंत्र सर्तक था तो यह घटना कैसे हुई।

द्रमुक की कनिमोई और ए. राजा ने ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार की पारदर्शिता की कमी को लेकर सवाल उठाए। कनिमोई ने जानकारी नहीं देने पर सरकार की आलोचना की और आरोप लगाया कि सुरक्षा एजेंसियों से जानकारी के अभाव में स्थानीय लोगों को भय में जीने को मजबूर किया गया।

उन्होंने कहा, "सरकार केवल

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

बस-ट्रक भिड़त में 6 तीर्थयात्रियों की मौत

देवघर, 29 जुलाई। देवघर-हंसडीहा मार्ग पर मोहनपुर प्रखंड के जमुनिया चौक के पास बस और ट्रक की टक्कर में बस सवार छह तीर्थयात्रियों की मौत हो गई। हादसे में चालक की भी मौत हो गई। 27 यात्री घायल हो गए। इनमें से आठ को एम्स रैफर किया गया है। उनका इमरजेंसी में इलाज चल रहा है। कुछ को आईसीयू में भर्ती कराया गया है। बाकी घायलों

- यात्री बस में 40 तीर्थयात्री देवघर से बासुकीनाथ जा रहे थे।

का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। देवघर से बासुकीनाथ जा रही यात्री बस में 40 से अधिक तीर्थयात्री सवार थे। यात्री बिहार और छत्तीसगढ़ के थे।

बस में सवार मोतिहारी निवासी सुरेन्द्र यादव ने बताया कि बस सामने से आ रहे सिलेंडर लदे ट्रक से टकरा गई। टक्कर लगते ही चालक सीट समेत

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

नेतृत्व सिर्फ श्रेय लेना नहीं होता, जिम्मेवारी भी स्वीकार करनी पड़ती हैं- प्रियंका गांधी

प्रियंका ने लोकसभा में यह भी कहा, "यहाँ बैठे हम सभी के पास सुरक्षा कवर है, पर, पहलगाम, जहाँ हमला हुआ, वहाँ एक भी सैनिक क्यों नहीं था"

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 29 जुलाई। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज लोकसभा में पहलगाम आतंकी हमले को लेकर मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला और सवाल उठाया कि यह हमला हुआ कैसे। उन्होंने बड़ी निपुणता के साथ उन कोशिशों का भी जवाब दिया, जिनमें हमले के पीड़ितों को सांप्रदायिक चश्मे से देखा जा रहा था। कुछ सांसदों द्वारा पीड़ितों को "हिंदू" कहे जाने पर उन्होंने कहा, वे "भारतीय थे"।

प्रियंका ने सुरक्षा में हुई चूक को लेकर सरकार को घेरा और पूछा कि जिस बैसारन वैली (पहलगाम) में हमला हुआ, वहां कोई सुरक्षा बल क्यों नहीं तैनात था।

- लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर हुई चर्चा के दौरान वायनाड सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने मोदी सरकार पर जबर्दस्त हमला बोला और कहा, गृह मंत्री अमित शाह इतिहास के पन्नों में चले गए, नेहरु, गांधी, मेरी माँ के आँसू, सब पर बोले, पर, असली सवाल का जवाब नहीं दिया कि पहलगाम अटैक क्यों और कैसे हुआ।
- प्रियंका ने कहा, शाह ने बताया यूपीए के 10 साल के राज में 25 हमले हुए, पर, 2020 से लेकर पहलगाम अटैक तक कश्मीर में ही 25 हमले हो चुके हैं। जब मुम्बई अटैक हुआ था तब उस समय के गृह मंत्री और मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया था। एक को छोड़ कर सारे आतंकी मारे गए थे।
- प्रियंका गांधी ने तंज कसा, 11 साल हो गए आपको सत्ता में, अब तो जिम्मेवारी लीजिए।
- प्रियंका ने कहा, अगर ऑपरेशन सिंदूर का लक्ष्य पाकिस्तान को सबक सिखाना था तो यह अधूरा है। पाक जनरल अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ लंच करते हैं। पाकिस्तान को सुरक्षा परिषद में एंटी-टैरर पैनल का मुखिया बनाया जाता है। इससे ऑपरेशन सिंदूर का लक्ष्य आहत हुआ है।
- लोकसभा में दिया गया प्रियंका गांधी का भाषण आज दिन भर सुर्खियों में रहा और सोशल मीडिया पर वायरल हुआ।

वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि सरकार कितने भी ऑपरेशन कर ले, लेकिन सच्चाई नहीं छुप सकती। उन्होंने कहा, "इस सदन में बैठे

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

छात्रसंघ चुनाव पर हाई कोर्ट ने सरकार से जवाब माँगा

जयपुर, 29 जुलाई। राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्रसंघ चुनाव नहीं कराने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन से एक अगस्त तक जवाब मांगा है। जस्टिस अनूप कुमार ढंड ने ये आदेश छात्र जय राव की ओर से दायर याचिका

- अदालत ने राज्य सरकार व विश्वविद्यालय प्रशासन को 1 अगस्त तक जवाब देने को कहा।

पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता शांतनु पारीक ने बताया कि विश्वविद्यालय के प्रत्येक छात्र को अपना प्रतिनिधि चुनने का संवैधानिक अधिकार है। अपने प्रतिनिधि के माध्यम से ही विद्यार्थियों की समस्याएं प्रशासन तक पहुंचती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी केरल विश्वविद्यालय

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)